



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2005/अग्रहायण 11, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2005/AGRAHAYANA 11, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2005

सं. 6-20/2005-बी एंड सीएस.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा 1(बी) के खण्ड (iv), (vii) तथा (viii) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- यह विनियम "अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 12)" कहा जाएगा।
- यह विनियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. "अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004" (2005 का 15) के विनियम 6 में उल्लिखित मौजूदा पैराग्राफों तथा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"ब्राडकास्टर, प्राधिकरण को अन्तरसंयोजन करार से संबंधित सूचना दो भागों अर्थात् भाग 'क' तथा भाग 'ख' में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रस्तुत करेंगे :—

(क) भाग 'क' में दो प्रतियों में विधिवत रूप से प्रमाणित मानक सम्बद्ध करार/सेवा संविदा/समझौता ज्ञापन अन्तर्विष्ट होगा।

(ख) भाग 'ख' में तालिका के रूप में अलग-अलग करारों, पते सहित संविदागत पार्टियों, करार द्वारा कवर किए जाने वाले सेवा क्षेत्र, इंटेग्रेटेड रिसीवर डिकोडर नम्बर तथा इंटेग्रेटेड रिसीवर डिकोडर को किराए पर लेने की शर्तें, संविदा संख्या, संविदा करने की तिथि, संविदा समाप्त होने की तिथि, चैनलों की संख्या, चैनलों का ब्यौरा, सब्सक्राइबर आधार, प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह प्रभार तथा नॉन कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (Non CAS) क्षेत्रों के मामले में रियायतों का ब्यौरा दिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत नॉन कैस क्षेत्रों में जो भी व्यवस्था की जानी अपेक्षित है उसके अलावा कैस (CAS) क्षेत्रों के लिए भाग 'ख' में प्रत्येक अलग-अलग चैनल, चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत, न्यूनतम सब्सक्राइबर गारंटी, यदि कोई हो, का ब्यौरा अतिरिक्त रूप में दिया जाएगा :

परन्तु इस विनियम के खण्ड 3 के अनुसार रजिस्टर रखने के लिए भाग 'ख' में जो भी सूचना दी जानी आवश्यक हो उसके अलावा प्राधिकरण समय-समय पर मानक सम्बद्ध करार/सेवा संविदा/समझौता ज्ञापन के ऐसे भागों के संबंध में जिनका उल्लेख भाग 'क' में किया गया है, असंकलित सूचना प्राप्त करने के लिए फार्मेट निर्धारित कर सकता है।

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि प्राधिकरण समय-समय पर डाटा अथवा सूचना दायर करने के तरीके, दायर किए जाने वाले फार्म या फार्मेट, दायर की जाने वाली प्रतियों की संख्या तथा अन्तरसंयोजन करार का ब्यौरा दायर करने से सम्बद्ध तथा उससे प्रासंगिक कार्यविधि से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं को विनिर्दिष्ट कर सकता है।"

3. "अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004" (2004 का 15) के विनियम 5 (बी) (3) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :

"जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर तथा अक्टूबर से दिसम्बर के पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान सभी अन्तरसंयोजन करारों में किए जाने वाली आशोधनों/संशोधनों तथा नए किए जाने वाले अन्तरसंयोजन करारों के मामले में, कलेण्डर वर्ष के क्रमशः 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर तथा 31 जनवरी अथवा इस विनियम के विनियम 6 के दूसरे प्रावधान के अनुसार समय-समय पर जैसा भी निर्धारित किया जाए।"

4. व्याख्यात्मक ज्ञापन

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है, जिसमें इस विनियम की पृष्ठभूमि दी गई है।

आदेशानुसार,

राकेश कक्कड़, कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार (बी एंड सीएस)

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/142/2005]

अनुलग्नक 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ब्राडकास्टर्स द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अन्तरसंयोजन करारों के पंजीकरण के प्रयोजन से 31-12-2004 को एक अलग विनियम अर्थात् "अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004 (2004 का 15)" अधिसूचित किया। यथासंशोधित अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004 (2004 का 15) के खण्ड 6 के साथ पठित खण्ड 5 के अनुसार ब्राडकास्टर्स को सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अन्तरसंयोजन करारों का ब्यौरा दायर करना आवश्यक है, जिसके भाग-क में संविदा/करार/समझौता ज्ञापन आदि के मानक फार्म और भाग-ख में अलग-अलग करारों के विशिष्ट ब्यौरे प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूप में दिया जाना अपेक्षित है तथा कलेण्डर वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद एक माह की समाप्ति पर उसमें तिमाही आधार पर अद्यतन करना भी आवश्यक है।

2. एक ब्राडकास्टर से उक्त विनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ क्योंकि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भाग-ख को प्रिंट रूप में दायर करने में कठिनाई हो रही थी। यह बताया गया कि वर्ष भर निरंतर नए करार किए जाते हैं/उनका नवीकरण किया जाता है/उनमें संशोधन किया जाता है। करारों की बड़ी संख्या को देखते हुए संशोधनों/परिवर्तनों पर नजर रखने की प्रक्रिया, अधिक श्रम तथा समय लगने वाला कार्य हो जाता है तथा प्रत्येक तिमाही के अंत में इन्हें प्रिंट रूप में दायर करने के लिए बड़ी मात्रा को दायर करना होता है। यह सूचित किया गया कि करारों के संपूर्ण अद्यतन ब्यौरे प्रत्येक तिमाही के अंत में इलैक्ट्रॉनिक रूप में दायर करना सरल है और यह अनुरोध किया गया कि उक्त विनियम में संशोधित किया जाए जिससे ब्राडकास्टर्स को तिमाही अद्यतन करते समय इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में भाग-ख के ब्यौरे दायर करने की स्वतंत्रता हो।

3. संशोधन के अनुरोध तथा डाटा की प्रमाणिकता तथा सुरक्षा के साथ समझौता किए बिना इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में इन्हें दायर करने की सुविधा का विकल्प के संबंध में टीवी, चैनलों के ब्राडकास्टर्स/वितरकों के साथ परामर्श करके जांच की गई। उक्त विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया कि करारों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रिंट रूप में इन्हें दायर करने में बहुत बड़ी मात्रा को सम्हालना पड़ता है। यह देखा गया कि इलैक्ट्रॉनिक रूप में इन्हें दायर करने के विभिन्न विकल्प जो 'सीडी-रोम', जिसमें सेवा प्रदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई-फाइलिंग तक की अपने विशिष्ट लाभ तथा हानियां हैं और साथ ही समय के साथ ये व्यावहारिक विकल्प बन सकते हैं। प्रस्ताव की जांच करते समय व्यापक तौर पर यह भी विचार किया गया कि समय-समय पर विनियमों में संशोधन का सहारा लेने के बजाय विनियमों में पर्याप्त लचीलापन लाने की आवश्यकता है, जिसमें न केवल किसी ऐसे रूप में, जिसमें इन्हें दायर किया जाता है बल्कि एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे कई अन्य प्रक्रियात्मक मामलों के संदर्भ में भी विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जा सके।

4. तदनुसार, ट्राई ने हर समय जब भी प्रक्रिया में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो विनियम में संशोधन करने के बजाय उक्त विनियम के वर्तमान खण्ड 6 में संशोधन करने का विनिश्चय किया ताकि प्राधिकरण एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से डाटा अथवा सूचना को दायर करने के तरीके, दायर किए जाने वाले फार्म तथा फार्मेट, दायर की जाने वाली प्रतियों की संख्या तथा अन्तरसंयोजन करारों के ब्यौरे को दायर करने से संबंधित अन्य ऐसे प्रक्रियात्मक मुद्दों के संबंध में कोई विशिष्ट प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सके। परिणामतः प्रस्तावित परिवर्तन के लिए इस विनियम के खण्ड 5 में भी संशोधन किया गया है। प्राधिकरण संशोधित विनियमों को अधिसूचित करने के बाद ब्राडकास्टर्स द्वारा इन्हें दायर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अलग से विनिर्दिष्ट करेगा।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2005

No. 6-20/2005-B & CS.—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with clauses (iv), (vii) and (viii) of Sub-section 1(b) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation, namely :

1. Short title, extent and commencement

- (i) This regulation shall be called "The Register of Interconnect Agreement (Broadcasting and Cable Services) (Second Amendment) Regulation, 2005(12 of 2005)"
- (ii) This regulation shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In regulation 6 of "The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting & Cable Services) Regulation, 2004" (15 of 2004), the following paragraphs and entries shall substitute the existing paragraphs and entries:-

"The broadcaster shall furnish to the Authority, the information relating to the interconnect agreement in two parts namely, Part A and Part B, as detailed below:-

- a) Part A containing the standard affiliation agreement/service contract/memorandum of understanding, duly authenticated in duplicate.
- b) Part B containing in tabular form the details of individual agreements, of contracting parties with addresses, service area covered by the agreement, integrated receiver decoder number and terms of hiring of integrated receiver decoder, contract number, date of entering contract, date of expiry of contract, number of channels, details of channels, subscriber base, charges per subscriber per month and discounts in the case of non-Conditional Access System (CAS) areas.
- c) Part B for CAS areas shall additionally contain details of maximum retail price of each individual channel, bouquet of channels, minimum subscriber guarantee if any, besides what is required to be provided in non-CAS areas under clause (b) above.

Provided that the Authority may from time to time prescribe formats for seeking disaggregated information on such parts of standard affiliation agreement/ service contract/memorandum of understanding referred to as Part A over and above and in addition to what is required to be furnished as Part B, as may be necessary, for maintaining the register as provided in clause 3 of this regulation.

Provided further that the Authority may from time to time specify the requirements, in regard to the manner of filing of data or information, the form or formats of filing, the number of copies to be filed, and other procedural aspects connected and incidental to the filing of details of interconnect agreements."

3. The entries relating to regulation 5 (b) (3) of "The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting & Cable Services) Regulation, 2004" (15 of 2004), shall be substituted by the following entries:

"30th April, 31st July, 31st October and 31st January of the calendar year for the modification/ amendments made in all interconnect agreements as well as new interconnect agreements during the preceding quarter of January to March, April to June, July to September and October to December, respectively or as may be specified from time to time in terms of the 2nd proviso to regulation 6 of this regulation".

4. **Explanatory Memorandum**

An explanatory memorandum dealing with the background of this regulation is annexed as Annexure "A"

By Order,

RAKESH KACKER, Acting Secy.-cum-Advisor (B & CS)

[ADVT-III/IV/Exty./142/2005]

Annexure A

Explanatory Memorandum

Telecom Regulatory Authority of India notified separate regulation namely, The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004". (15 of 2004) on 31.12.2004, for the purpose of registration of interconnect agreements entered into by broadcasters with the service providers. In terms of clause 5 read with clause 6 of "The Register

of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004". (15 of 2004) as amended, the broadcasters are required to file details of interconnect agreements entered into with the service providers in part A containing standard forms of contract/agreement/MOU etc and in Part B containing specified details of individual agreements both in print and electronic form with quarterly updation at the expiry of one month from the end of each quarter.

2. A proposal for amendment to the above regulation was received from a broadcaster expressing difficulties in filing in print form of part B at the end of every quarter. It was indicated that new agreements are entered /renewed/modified continuously throughout the year. In view of a large number of agreements involved, the process of tracing amendments /changes becomes laborious and time consuming and the filing in print form at the end of every quarter becomes very voluminous. It was pointed out that it is easier to file the entire updated details of agreements at the end of every quarter in Electronic form and requested for amendment to the above regulation to provide freedom to the broadcasters to file details of part B in electronic form at the time of quarterly updation.

3. The request for amendment and options for facilitating filing in electronic form without compromising on authenticity and security of data was examined in consultation with major broadcasters/distributors of TV channels. It has been experienced during the implementation of above regulations that the filing in print form, in view of the large number of agreements, becomes very voluminous. It was noted that various options of filing in electronic form ranging from filing in CD-ROM bearing the signature of the authorized representative of the service provider to e-filing with digital signature have distinct merits and demerits and could become a viable option over a period of time. While examining the proposal it was also viewed from a broader angle that the regulations would need to be made flexible enough to facilitate adopting a particular procedure not only with reference to a particular form in which the filing is to be done but also with reference to a number of other procedural matters, through a simplified process, instead of resorting to the need to amend the regulations time and again.

4. Accordingly TRAI has decided to amend the existing clause 6 of the above regulation so as to enable the Authority to specify a particular procedure in regard to the manner of filing of data or information; to the form or formats of filing; to the number of copies to be filed; and, to such other procedural issues connected to the filing of details of interconnect agreements through a simplified process instead of the need to amend the regulation every time whenever a change in procedure is necessitated. Consequential amendment in clause 5 of the regulation has also been made to give effect to the proposed change. The Authority would separately be specifying the procedure to be adopted by the broadcasters for the filing(s) due after amended regulations are notified.